Indian J. Soc. & Pol. 07 (02) :91-94 : 2020 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 July 2020 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

भारत, नेपाल और नाथ पंथ

महेंद्र कुमार सिंह[1]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, उ0प्र0,भारत

ABSTRACT

भारत और नेपाल के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा. या युं कहे की मित्र राष्ट्र, निकट सहयोगी कहे जाने वाले दो पड़ोसी देशों की सदियों पुरानी दोस्ती और आम तौर पर मधुर रहने वाले रिश्तों को किसी की नजर लग गयी. दोनों देशों के संबंध दिनों–दिन बदतर होते जा रहे हैं। अभी भारतीय क्षेत्र को अपना बताकर नेपाल द्वारा नया राजनीतिक मानचित्र जारी करने और नेपाल में कोरोना संकट बढ़ाने में भारत पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आरोपों से उपजा विवाद थमा भी न था कि ओली ने सनातनी हिन्दू आस्थाओं के अवलम्ब प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को लेकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। वास्तव में, भारत और नेपाल केवल पड़ोसी देश नहीं हैं बल्कि इनका सदियों पुराना नाता है जो इन्हे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक रूप से जोड़ता है। नेपाल से भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का है। नेपाल भारत के लिए सामरिक और रणनीतिक महत्व का है। भारत के पांच राज्यों की सीमा नेपाल से लगी है इस कारण नेपाल में उत्पन्न अस्थिरता भारत को भी प्रभावित करती है। भारत के पास इस पर्वतीय देश से संबंध मजबूत करने के लिए तमाम कूटनीतिक प्रयासों से इतर एक बेहद मजबूत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माध्यम भी है। एक 'आउट ऑफ बॉक्स' सुझाव और भी है जिससे दोनों देशों की जनता को जोड़ा जा सकता है वह है 'नाथ पंथ'। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत , नेपाल सम्बन्धों के तात्कालिक स्वरूपों का अध्ययन करते हुए नाथ पंथ को एक उम्मीद के रूप में देखने का प्रयास किया गया है।

KEYWORDS: *अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, भारत, नेपाल, नाथ पंथ, कम्यूनिस्ट पार्टी*

बिना किसी एतिहासिक तथ्यों या पुरातात्विक प्रमाणों के केपी शर्मा ओली का यह बयान सतही तौर पर तो सहज हास्य पैदा करता है, लेकिन गंभीरता से सोंचे तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुचता है और अगर इस बयान के पीछे झांके तो नेपाली प्रधानमंत्री की राजनीतिक मजबूरी, की बयानी भी है। ओली अपनी पार्टी में ही बुरी तरह से घिरे हुए हैं। उन्हीं की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में उनकी बहुत आलोचना हुई और अब इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही है। आर्थिक मोर्चे पर भी वे कुछ ठोस नहीं कर पा रहे और कोविड 19 से निपटने में नाकामी को लेकर भी उन्हें विरोध झेलना पड़ा है। ऐसे समस्याप्रद काल में ओली ने प्रखर राष्ट्रवाद को अपना हथियार बनाया है।

ओली का नया मानचित्र : नेपाली राष्ट्रवाद को हवा देने की कोशिश

हाल के दिनों में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद जो एक बार फिर सतह पर उभर कर आया है नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे को लेकर है। इस मानचित्र में भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है। भारत के उत्तराखंड राज्य के बॉर्डर पर नेपाल–भारत और तिब्बरत के ट्राई जंक्शन पर स्थित कालापानी करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का कहना है कि करीब 35 वर्ग किलोमीटर का यह इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। उधर, नेपाल सरकार का कहना है कि यह इलाका उसके दारचुला जिले में आता है। वर्ष 1962 में भारत–चीन के बीच युद्ध के बाद से इस इलाके पर भारत के आईटीबीपी के जवानों का कब्जा है। दोनों देशों के बीच विवाद महाकाली नदी के उद्गम स्थल को लेकर है। यह नदी कालापानी इलाके से होकर गुजरती है।

भारत और नेपाल के बीच ये सीमा विवाद काफी पुराना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1816 में सुगौली की संधि से हुई थी। इस संधि के अनुसार, महाकाली नदी के पूर्व में पड़ने वाली सारी जमीन नेपाल के हिस्से में आती है। इस संधि के बाद, नेपाल का दावा है कि लिपुलेख, लिंपियाधुरा और और कालापानी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि, हकीकत ये है कि भारत की सीमा से लगे ये विवादित क्षेत्र, महाकाली नदी के उद्गम स्थल से दक्षिण पूर्व इलाके में पड़ते हैं। नेपाल के इस दावे का भारत यह कह कर प्रतिरोध करता रहा है कि सुगौली की संधि के अंतर्गत इस धारा के उत्तर वाले हिस्से की सीमा को पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्नीसवीं सदी के आखिरी दशक से प्रशासनिक एवं राजस्व के रिकॉर्ड बताते हैं कि कालापानी इलाका वास्तव में भारत के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा रहा था।

भारत के प्रति नेपाल के रवैये में आई आक्रामकता को कुछ जानकर मोदी सरकार की नेपाल नीति की विफलता मान रहे हैं, कुछ इस प्रकरण के पीछे नेपाल की राजनीति के अंदरूनी दाव–पेंच कारक मान रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में प्रधानमंत्री ओली के तीखे व् अटपटे भारत विरोधी बयान नेपाल की राजनीति में चीन के हस्तक्षेप की चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहे हैं. और ज्यादातर जानकारों का मानना है की वों ये चीन के इशारे पर ही भारत को उकसाने के लिए ही कर रहे है.

हिमालय की वादियों में चल रहा 'नया ग्रेट गेम'

तेजी से बदलते नेपाल के रवैये को समझने के लिए अक्टूबर 2019 में घटित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को याद करना पड़ेगा, पिछले साल अक्टूबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिंगपिंग नेपाल

1: Corresponding Author

के दौरे पर थे। 1996 में जियांग जैमिन के बाद ये पहले चीनी राष्ट्रपति थे जिन्होंने नेपाल का दौरा किया। इस दौरान नेपाल के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए जिसमें चीनी राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षी योजना 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिव' शामिल थी। हालांकि शेष दक्षिण एशिया के देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव की तुलना में चीन द्वारा नेपाल में निवेश काफी कम रहा है। लेकिन इस दौरे ने ये सुनिश्चित किया की आने वाले वक्त में ये स्थिति बदलती दिखाई पड़ेगी और हुआ भी वही।

दरअसल हिमालय के परिदृश्य पर आज एक नया ग्रेट गेम खेला जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका, नेपाल से सम्बंध मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा ताकि उसे अपनी इंडो–पैसिफिक स्ट्रेटजी को बल मिल सके। इसी स्ट्रेटेजी के तहत अमेरिका ने मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन के तहत 500 मिलियन डॉलर की सहायता की पेशकश की है नेपाल में रोड और बिजली परियोजनाओं के लिए.चीन के 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिव' और दूसरे प्रोजेक्ट से उत्पन्न होती सामरिक चिंता के सापेक्ष अमेरिका दृढ़ प्रतिक्रिया देना चाहता है। ताकि क्षेत्र में शक्ति संतुलन स्थापित रह सके।

अमेरिकन नीति के संदर्भ में विशेषज्ञों का मानना है कि भारत, अपना समर्थन अमेरिका के इंडो– पैसिफिक स्ट्रेटजी को देगा, जिससे वहां चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। वजह भी वाजिब है क्योंकि नई दिल्ली इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिये बीजिंग के बढ़ते प्रभाव की बराबरी नहीं कर पा रहा। आज नेपाल में हो रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है। यही नहीं वह नेपाल का विश्व मे दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।

गौरतलब है कि भारत ने भी नेपाल के आधारभूत विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुये उसे विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, आवास, शोध, प्रशिक्षण, संस्कृति, खेल आदि क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में सहयोग किया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि नई दिल्ली वह सुसंगत नीति बनाने में विफल रही, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को क्षेत्रीय विकास से जोड़ा जा सके।

ध्यातव्य है कि नेपाल हमेशा से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारत के नजदीक रहा है। लेकिन नेपाल चीन के लिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि इसकी सीमाएं तिब्बत से लगी हैं। चीन, नेपाल में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिये उसे एक श्बफर जोनश की तरह स्थापित करना चाहता है। इससे उसके दो बड़े हित सधते हैं, एक तो किसी पश्चिमी देश द्वारा चीन को अस्थिर करने की सम्भावना न्यून होती है दूसरा, भारत पर सामरिक दबाव बनाने उसकी चिर अभिलाषा पूरी होती है।

भारत–नेपाल : बदलते आयाम

वास्तव में, भारत और नेपाल केवल पड़ोसी देश नहीं हैं बल्कि इनका सदियों पुराना नाता है जो इन्हे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक रूप से जोड़ता है। नेपाल से भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का है। नेपाल भारत के लिए सामरिक और रणनीतिक महत्व का है। भारत के पांच राज्यों की सीमा नेपाल से लगी है इस कारण नेपाल में उत्पन्न अस्थिरता भारत को भी प्रभावित करती है। इस सीमा विवाद से परे, भारत और नेपाल का आपसी सहयोग का लंबा इतिहास रहा है और दोनों ही देश, इससे पहले उस वक्त के सीमा विवादों को कूटनीतिक संवाद के माध्यम से सफलतापूर्वक हल करते आए हैं. 1981 में भारत और नेपाल ने मिल कर साझा तकनीकी स्तरीय सीमा समिति का गठन किया था. इस समिति की जिम्मेदारी दोनों ही देशों की लगभग 1850 किलोमीटर लंबी सीमा का स्पष्ट रूप से विभाजन करना था। भारत और नेपाल का ये साझा प्रयास बेहद सफल रहा था। दोनों ही देशों ने आपसी सहमति से वर्ष 2007 तक अपनी 98 प्रतिशत सीमाएं स्पष्ट रूप से रेखांकित कर ली थीं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि दोनों ही देश उसके बाद से कई मौकों पर इस बात को लेकर सहमति जता चुके हैं कि दोनों देशों की सीमा के बचे हुए विवादित हिस्सों के निपटारे के लिए एक उच्च स्तरीय व्यवस्था की जाए।

ऐसे में, भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं के बीच स्थित इस जगह को लेकर भारत और नेपाल के बीच जो ताजा विवाद उठ खड़ा हुआ है, उसके कारण पहले भी दोनों देशों के रिश्ते पटरी से उतरने के कगार तक पहुंचते रहे हैं। भारत की सरकार ने सीमा तक सड़क निर्माण को महज कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने वाली सड़क का नाम दिया है। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। अब तक यहां जाने के लिए केवल दो ही रास्ते उपलब्ध थे, या तो यहां नाथू–ला के रास्ते जाया जा सकता था या फिर नेपाल के रास्ते। दोनों ही मार्ग बेहद मुश्किल हैं। धारचुला तक इस सड़क के बन जाने से कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाना बेहद आसान भी हो जाएगा और इससे काफी समय भी बचेगा।

इन कारणों के अतिरिक्त, भारत के इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखने के कई अन्य स्पष्ट लाभ भी हैं। इस सड़क के बन जाने से भारत और चीन के बीच इस रास्ते से व्यापार में काफी वृद्धि होने की संभावना है। चीन के साथ लगी सीमा पर संपर्क बेहतर होने का भारत को सामरिक लाभ भी होगा। 2017 में संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि सीमा के आस पास के इलाकों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास करना बेहद महत्वपूर्ण है। इससे, कुछ, 'परेशान करने वाले पड़ोसी देशों' के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने में मदद मिलेगी।

नेपाल में चीन की 'घुसपैठ'

भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो सकती है। मगर, नेपाल का हालिया प्रतिकार उस समय देखने में आया है, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर दो जगहों पर संघर्ष देखने को मिला था।

कालापानी सीमा को लेकर भारत की चिंताओं को थल सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे ने उस वक्त बखूबी रेखांकित किया था, जब उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि नेपाल ने सीमा पर ये विवाद, 'किसी अन्य देश के कहने पर खड़ा किया हो.' थल सेनाध्यक्ष

के इस बयान का इशारा चीन की तरफ था। भारत की सुरक्षा और सामरिक संस्थान देर से ही सही लेकिन अब हिमालय के अंचल में चल रहे नए 'ग्रेट गेम' को समझ गए हैं।

भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो सकती है। मगर, नेपाल का हालिया प्रतिकार उस समय देखने में आया है, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर दो जगहों पर संघर्ष देखने को मिला था। 10 मई 2020 को भारत और चीन और भारत के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में पैंगॉन्ग त्सो झील के पास, सिक्किम के नाकू ला में संघर्ष हुआ था। इसके ठीक पहले 9 मई को नेपाल ने आधिकारिक रूप से भारत के लिपुलेख सीमा के लिए सड़क के उद्घाटन को एकतरफा कार्रवाई बताया था और भारत को चेतावनी दी थी वो नेपाल की सीमा के भीतर कोई गतिविधि न करे।

भारत और नेपाल के बीच अविश्वास की इस बढ़ती खाई के पीछे, नेपाल के घरेलू मामलों में चीन के बढ़ते दखल को जिम्मेदार बताया जा रहा है। चीन, पिछले एक दशक से नेपाल के वामपंथियों को समर्थन देता आ रहा है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के साथ, चीन का नेपाल की अंदरूनी राजनीति में दखल शीर्ष पर पहुंच गया था। नेपाल के चीन के प्रति बढ़ते झुकाव की इस सोच को तब और बढ़ावा मिला, जब 2015 में नेपाल के नए संविधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत ने नेपाल की सीमा की नाकेबंदी कर दी थी।

हालिया वर्षों की घटनाओं को देखें तो ऐसा आभास होता है कि नेपाल जो कि एक लैंडलॉक्ड देश है और वो भारत से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। 2015 में भारत की तरफ से अघोषित नाकाबंदी की गई थी और इस वजह से नेपाल में जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई थी। तब से दोनों देशों के बीच संबंधों में वो भरोसा नहीं लौट पाया है। भारत, नेपाल के नए संविधान से संतुष्ट नहीं था। कहा जा रहा था कि नेपाल ने मधेसियों के साथ नए संविधान में भेदभाव किया है। मधेसी भारतीय मूल के हैं और इनकी जड़ें बिहार और यूपी से हैं। हालांकि नेपाल ने संविधान में कोई बदलाव नहीं किया और भारत को नाकाबंदी बिना कोई कामायाबी के खत्म करनी पड़ी थी।

रिश्तों पर लगे ग्रहण से कैसे निपटे

अपने अन्य पड़ोसियों की अपेक्षा नेपाल के साथ भारत के रिश्ते काफी मधुर और गर्माहट भरे रहे हैं। रोटी–बेटी का रिश्ता रहा है। भारत और नेपाल दोनों सम्प्रमभु राष्ट्रो हैं लेकिन दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। ऐसे पूरक जो एक–दूसरे के हित–अहित को नजरअंदाज कर कभी कोई निर्णय ले ही नहीं सकते।

भारत को नेपाल के साथ संबंध वापस पटरी पर लानाने के लिए कई दिशा में कदम उठाने की जरुरत है. जरूरत है नाकाबंदी से पैदा हुए अविश्वास को दुबारा कायम करने कीप आर्थिक निवेश को बड़ा कर क्षेत्रीय सहयोग को बढाने की जरूरत है नेपाल की जनता को विश्वास में लेने की कि भारत ही उनका वास्तविक हितैषी है बड़े भाई वाले व्यवहार को छोड़ बराबरी का सन्देश देने कीप्सीमा विवाद को बातचीत, आपसी समझदारी और कुशलता से हल करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे भारत के एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति होने की छवि को मजबूती मिलेगी। भारत एक ऐसी शक्ति के तौर पर उभर सकेगा, जो अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों की चिंताओं की अनदेखी नहीं करता है। इसी तरह नेपाल को भी यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री ओली के हालिया बयानों की तरह का भारत के प्रति उनका बेकाबू रवैया, उन्हें ऐसे विवादों के समुचित समाधान की दिशा में नहीं ले जाएगा।

नेपाल में नाथ पंथ

नेपाल से सदियों पुराने रिश्तों के बावजूद हाल के वर्षों में बार–बार कड़वाहट के अनुभवों की वजह भले किसी तीसरे देश की स्वाार्थपरता हो लेकिन इसका समाधान भारत के पास ही है। भारत के पास इस पर्वतीय देश से संबंध मजबूत करने के लिए तमाम कूटनीतिक प्रयासों से इतर एक बेहद मजबूत सांस्कृतिक और आध्यत्मिक माध्यम भी है। एक 'आउट ऑफ बॉक्स' सुझाव और भी है जिससे दोनों देशों की जनता को जोड़ा जा सकता है, नेपाल में राजशाही के अंत और उसके बाद साम्योवाद के नाम पर बनी सरकारों ने चीन के प्रभाव में कई काम किए। लेकिन ये सरकारें भी नेपाल की जनता के मन और दिल से गुरु गोरखनाथ को निकाल नहीं पाईं। उन्होंजने 2006 के बाद से नेपाली करेंसी से गुरु गोरखनाथ का चित्र और चरण पादुका तो हटा दी लेकिन उनके द्वारा नेपाल का एकीकरण करने वाले महाराणा पृथ्वीकनारायण शाह को दी कटार का प्रतीक हटाने का साहस नहीं जुटा पाईं। नेपाल के कोने–कोने में गुरु गोरखनाथ, उनके गुरु मत्स्येन्द्रनाथ की कहानियां प्रचलित हैं। वहां विभिन्न स्थानों पर दोनों महायोगियों के तपस्थेल हैं। मंदिर हैं। नाथ योगियों की परम्परा है।

तमाम उतार–चढ़ावों के बावजूद आज भी नेपाल शाही परिवार सहित बड़ी संख्यात में नेपाल के नागरिकों की खिचड़ी गोरखनाथ मंदिर में चढ़ती है। नेपाल शाही परिवार गुरु गोरखनाथ को अपना राजगुरु मानता रहा। यही नहीं स्वतंत्र भारत में भी नाथपंथ के संतों ने समय समय पर तत्कालीन सरकारों को नेपाल में हो रहे घटनाक्रमो के बारे में आपने सुझाव व् विचार दिए लेकिन उनके नेपाल सम्बंधित विचारों की अनदेखी की गयी और उसका नतीजा आज सबके सामने है।

यह नाथपंथ का नेपाल में प्रभाव और तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ के प्रति आदर ही था कि 1950 के दशक में शाह राजवंश और राणा शासकों में जारी सत्ता संघर्ष के दौर में तत्कालीन सरकार को उनकी मदद लेनी पड़ी। ब्रह्मलीन योगी अवेद्यनाथ के शब्दों में नेपाल 'हमारा पड़ोसी मित्र राष्ट्र ही नहीं समान और साझा सांस्कृतिक विरासत के कारण सहोदर भाई जैसा एकात्म राष्ट्र है।'

आज के चुनौतीपूर्ण समय में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के 46 वें वार्षिक अधिवेशन में ग्वालियर, मध्य प्रदेश में अप्रैल 23, 1961 के अध्यक्ष पद से अपने सम्बोधन में महंत दिग्विजयनाथ की नेपाल के प्रति उस समय भारत की नीतियों पर चिंता और चेतावनी याद आती है। वह कहते हैं वर्तमान स्थिति में

शासकों के लिए यही उचित है कि वे नेपाल के हिन्दू–राज्य के साथ संयुक्त मोर्चा स्थापित करें। क्योंकि भारत और नेपाल के नागरिक एक ही धर्म के अनुयायी एवं एक ही जीवन प्रणाली के आराधक है। किंतु दुर्भाग्य यह है कि हमारे कांग्रेसी शासक नेपाल के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, वह पूर्णतः अव्यवहारिक है। वो आगे कहते हैं कि षहिन्दू महासभा, हिन्दू संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिये कटिबद्ध है और उसे विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हिन्दू के प्रति ममता है। इसलिए विश्व के एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल के प्रति भी उसका ममत्व स्वाभाविक है। इसके साथ ही साथ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि महाराजाधिराज नेपाल ने अपने राज्य के संविधान में नेपाल को स्पष्ट शब्दों में हिन्दू राष्ट्र घोषित किया है जो आर्य संस्कृति एवं हिन्दू राज्य की स्थापना के लिए कटिबद्ध है।

दिग्विजयनाथ जी आगे कहते हैं कि यदि हम नेपाल के साथ अपने धार्मिक और सांस्कृतिक बन्धनों को छोड़ भी दें तब भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से यह अनिवार्य है कि हम नेपाल के साथ मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण सम्बंध स्थापित करें, क्योकि नेपाल ही एकमात्र राज्य है जो विदेशी आक्रमण के समय हमारी सहायतार्थ आगे आ सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे कांग्रेसी शासक महाराजा नेपाल और नेपाल की जनता को अपने गलत कर्मों और रीति–निति से क्षुब्ध बना रहे। यह सब कुछ लोकतंत्र के नाम की आड़ लेकर किया जा रहा है। यह वो समय था जब नेपाल के तत्कालीन राजा महेंद्र ने राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिग्विजय नाथ जी नहीं चाहते थे कि नेपाल पर लोकतंत्र और सेकुलरिज्म थोपा जाए।

अपने भाषण में वो कहते हैं हमें हिन्दू महासभा की ओर से नेपाल के महाराजाधिराज और नेपाल की हिन्दू जनता के समक्ष यह स्पष्ट करने के लिये एक सद्भावना मंडल भेजना चाहिए कि भारत के हृदय में उनके प्रति पूर्ण सद्भावना है और वे नेपाल राज्य के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी भी इन्हीं विचारों का समर्थन करते हुये कहते हैं, नेपाल की सुदृणता तथा मैत्री– भावना एवं श्रीवृद्धि ही भारत के हित में हैं, क्योंकि उत्तरी सीमाओं पर यह ही हमारा एकमात्र शुभेच्छु और सहयोगी है। दिग्विजयनाथ जी की तरह ही महंत अवैद्यनाथ जी और महंत आदित्यनाथ ने बार–बार भारत सरकार को नेपाल में हो रहे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के बारे में सचेत करते हुये आगाह करते रहे हैं कि बदलते घटनाक्रम जैसे माओवादी गतिविधियां, आईएसआई की पैठ और धर्मांतरण हमारे हित में नहीं हैं। 2006 में महंत अवैद्यनाथ ने कहा था 1990 के संविधान के अनुसार नेपाल में लोकतंत्र और हिन्दू–अधिराज्य कायम रहे। 2006 में ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था भारत सरकार को कोई निर्णय लेने के पूर्व 31 जुलाई 1950 की संधि जिसके अनुसार दोनों देश एक दूसरे की सम्प्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है, का सम्मान करना चाहिए। अन्यथा हमारा एक परंपरागत मित्र देश जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से ही नहीं राजनीतिक रूप से भी हमारा सहयोगी रहा है, हमसे विलग हो कर हमारे शत्रुओं के साथ जा सकता है, जिससे भारत की अपूर्णीय क्षति सुनिश्चित है। इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि हम केवल लोकतंत्र के नाम पर ही नहीं वस्तुस्थिति के सम्यक आंकलन और उसके अनुसार एक न्यायसंगत व्यवहारिक निष्कर्ष पर पहुंचे, जिससे दोनों देशों का परम्परागत सौहार्द और सदभाव भी बना रहे और वहॉ के प्रवर्तमान संविधान का भी सम्मान हो।

नेपाल से सम्बवन्धि ठीक रखने हैं तो इसका एक सरल मार्ग गुरु गोरखनाथ का नाथ पंथ भी हो सकता है। कुटनीतिक रास्तो तो अलावा भारत के पास एक 'सॉफ्ट पॉवर' है नाथ पंथ के रूप में. अभी भी लाखो की संख्या में नाथ पंथ के अनुयायी नेपाल में रहते है. गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें सहायक सिद्ध हो सकते हैप्यह वो सूत्र है जिससे बंधकर नेपाल की जनता और वहां का शासक वर्ग हमसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नेपाल और नाथ पंथ एक–दूसरे में ऐसे रचे–बसे हैं कि वर्तमान शासक वर्ग भले चीन की भाषा बोलने लगे लेकिन नेपाल की जनता हमेशा भारत के स्वहर में ही स्वर मिलाकर बोलेगी।

REFERENCES

सिंह,पद्मजा (2019) *नेपाल में नाथ पंथ* अप्रकाशित शोधग्रंथ,

आदित्यनाथ, योगी, (2006) *हिन्दू राष्ट्र नेपाल : अतीत और वर्तमान,*

सिंह, जनरल भरत केशर *राष्ट्र संत महंत अवेधनाथ* (स्मृतिग्रंथ)

https://www.researchgate.net/publication/294260264_The_Great_Himalayan_Game_India_and_China_Rivalry_in_Nepal

https://www.orfonline.org/research/41945-why-india-needs-to-safeguard-its-ties-with-nepal/

https://swarajyamag.com/politics/political-continuity-in-india-will-cement-indo-nepalese-relations-critical-for-indias-himalayan-states

https://www.fes-asia.org/news/geopolitics-and-nepals-future-after-the-pandemic/

https://www.bbc.com/hindi/india-53022535

https://thediplomat.com/2019/10/high-expectations-as-chinas-xi-lands-in-nepal/

https://www.asiatimes.com/2019/10/opinion/new-great-game-in-the-himalayan-landscape/

https://kathmandupost.com/columns/2020/07/19/is-there-a-china-connection